जून 2021
खंड - XXXVII | अंक - II

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- मूल्य श्रृंखला विकास: भारत और आसियान देशों के लिए अवसर
- भारत से कृषि निर्यात को बढ़ाना
- भारत-बांग्लादेश साझेदारी को सुदृढ़ बनाना
- भारतीय परिधान उद्योग
- भारत के जीवीसी एकीकरण को सुगम बनाने के लिए नीतिगत माध्यम के रूप में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

मूल्य श्रृंखला विकास: भारत और आसियान देशों के लिए अवसर

एशिया का दक्षिणपूर्वी क्षेत्र दुनिया में वर्तमान में सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है और इसकी वजह है, यहां का मजबूत विनिर्माण क्षेत्र। अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और विपुल प्राकृतिक संसाधनों के कारण दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों का संघ (आसियान) दुनिया में प्रमुख क्षेत्रीय गठजोड़ों में से एक है। यहां का मौजूदा परिवेश इस क्षेत्र के बाजारों से, तैयार माल के आयात, विनिर्माण और शिपिंग के अनुकूल है।

इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और भी महत्त्व मिला है और आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के साथ यह तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में, कुल वैश्विक व्यापार में आसियान की 7.4% की हिस्सेदारी है। निवेश की बात करें तो कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे आसियान देशों में 2019 में अब तक का सबसे ज्यादा एफडीआई आवक दर्ज किया गया। हाल ही में यूएस-चीन व्यापार संबंधों में तनाव के चलते बहुराष्ट्रीय उद्यमों के स्थान परिवर्तन करने और अन्य आसियान देशों व जापान से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मिले बड़े निवेश के कारण; कंबोडिया और वियतनाम में निवेश बढ़ गया है।

भारत-आसियान व्यापार और निवेश

आसियान, भारत के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक अपने आर्थिक हित और रणनीतिक पहुंच बनाने के लिए एक रणनीतिक जरिया है। आसियान और भारत में वैश्विक जनसंख्या की एक चौथाई से ज्यादा यानी कुल 2.02 बिलियन आबादी है, और इसकी जीडीपी 6.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, इसलिए ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक हैं। भारत और आसियान देशों को एक-दूसरे के पूरक बनाने वाले कई पहलू हैं। हाल के कुछ वर्षों में, आसियान भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार 2010 में 52.6 बिलियन यूएस डॉलर था, जो 2019 में बढ़कर 91.3 बिलियन यूएस का डॉलर हो गया।

निवेश की बात करें तो, थोड़ा बहुत सिंगापुर और कुछ हद तक, मलेशिया द्वारा भारत में अच्छा निवेश किया गया है, तथापि अन्य आसियान देशों के साथ भारत के निवेश संबंध अभी तुलनात्मक रूप से भुनाए नहीं जा सके हैं। है। हाल के वर्षों में, भारत से सीएलएमवी देशों में निवेश में रुचि बढ़ी है। इसकी मुख्य वजह है, उनके तेजी से बढ़ते बाजार, सस्ता श्रम और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार।

आसियान और भारत का जीवीसी विश्लेषण

प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात के मामले में आसियान देशों, भारत और चीन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण से पता चला है कि चीन के निर्यातों का 57.5% और आसियान के निर्यातों का 51.3% निर्यात, मध्य और उच्च तकनीक वाली वस्तुओं से संबंधित है; जबकि भारत से केवल 32.9% निर्यात ही मध्य और उच्च तकनीक वाली वस्तुओं के रहे। वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में बढ़ते एकीकरण ने भारत और कुछ आसियान देशों के लिए नई राहें खोल दी हैं। इससे संसाधनों और निम्न प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातों पर निर्भरता को कम करने और मध्य से उच्च तकनीकी विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं के प्रमुख निर्यातक बनने में मदद मिलेगी।

हालांकि आसियान में जीवीसी भागीदारी 1990 के स्तर की तुलना में बढ़ी है, तथापि यह 2000 और 2010 से कम ही रही। 2000 से 2018 तक जीवीसी में कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम सभी की भागीदारी घटी है। जीवीसी में भारत की भागीदारी दर भी 2010 के 45% से घटकर 2018 में 41% रह गई।

तालिका 1: आसियान और भारत में जीवीसी भागीदारी दर

देश	1990	2000	2010	2018
ब्रूनेई	35.5%	31.9%	45.6%	49.7%
कंबोडिया	35.4%	35.2%	36.3%	31.0%
इंडोनेशिया	38.8%	46.0%	51.3%	50.0%
लाओ पीडीआर	38.1%	43.0%	37.9%	32.0%
मलेशिया	61.0%	63.4%	67.3%	64.0%
म्यांमार	32.3%	44.0%	45.0%	38.9%
फिलीपींस	62.5%	63.3%	63.3%	57.5%
सिंगापुर	75.5%	79.1%	76.5%	75.5%
थाइलैंड	44.7%	53.5%	54.4%	51.8%
वियतनाम	40.8%	45.6%	61.6%	49.3%
आसियान	56.2%	61.3%	63.8%	60.8%
चीन	29.5%	37.9%	46.8%	44.6%
भारत	30.4%	38.6%	45.0%	41.4%

स्रोतः अंकटाड एओरा डेटाबेस और इंडिया एक्ज़िम बैंक का विश्लेषण

बैकवार्ड लिंकेजों के जरिए जीवीसी में भागीदारी को मापने के लिए सकल निर्यातों की विदेशी मूल्यवर्धित (एफवीए) सामग्री को मानदंड माना गया। विश्लेषण में पाया गया कि जीवीसी में भारत का एकीकरण कम (14.1%) रहा। दूसरी ओर, आसियान में उच्च बैकवार्ड लिंकेज देखा गया। 2018 में एफवीए सकल निर्यातों का 35.7% रहा। सिंगापुर या वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए निर्यातों में एफवीए का हिस्सा या बैकवार्ड भागीदारी अधिक है, क्योंकि वे अपने निर्यातों के लिए विदेशी सामग्री पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

आसियान के साथ भारत और चीन की जीवीसी भागीदारी के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि चीन के पास बड़े और विविध विनिर्माण आधार और उच्च तकनीक वाले उत्पादों की असेंबलिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता है। चीन, आसियान देशों से बड़े पैमाने पर मध्यवर्ती उत्पाद खरीदता है। आसियान के लिए सकल मूल्यवर्धित निर्यातों के लिए आयात की जाने वाली सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1990 में इसमें चीन की हिस्सेदारी 2.7% थी, जो 2018 में बढ़कर 15.6% हो गई। आसियान निर्यातों के लिए आयात की जाने वाली सामग्री के लिए भारत 12वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 1990 की 0.7% से बढ़कर 2018 में 2.3% रही।

भारत और आसियान के बीच मूल्य श्रृंखला का विकास: प्रमुख क्षेत्र

मूल्य श्रृंखलाओं का विकास आसियान देशों के साथ भारत की गतिविधियां बढ़ाने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। भारत और आसियान देशों के बीच औद्योगिक विनिर्माण के विभिन्न चरणों में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला बनाने से पूरे भारत और आसियान के बीच उत्पादन केंद्रों को निर्बाध रूप से बदला जा सकेगा। यहां भारत और आसियान देशों के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) के विकास से संबंधित कुछ रणनीतिक क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी क्षेत्र में छोटे-से-छोटे उत्पादों से लेकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक विभिन्न वस्तुओं का विनिर्माण होता है। इसके बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक्स उन उद्योगों में से एक है जहां भारत में 40 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का व्यापार घाटा दर्ज किया गया है तथा इस आंकड़े के और बढ़ने की आशंका है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारत आयात के लिए चीन पर बड़े पैमाने पर निर्भर है।

आसियान के कई देश, इलेक्ट्रॉनिक्स के अच्छे विनिर्माण केंद्र हैं। इसके अलावा, आसियान देशों में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने अपने उत्पादों का विविधीकरण किया है। वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से लेकर पुर्जों तक का उत्पादन करते हुए मध्य से लेकर उच्च तकनीकी उत्पादों तक का उत्पादन कर रही हैं। साथ ही, उत्पादन चक्र के सभी पहलुओं के परिचालन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के पूंजी और श्रम-गहन दोनों चरणों में उत्पादन करती हैं। उत्पादन के सभी पहलुओं को एक साथ संचालित करने के साथ ही, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के पूंजीगत और श्रमगत उत्पादों के चरणों में भी लगी हुई हैं। आसियान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कंपनियों का एक लाभ यह भी है कि वे सर्वोत्तम तकनीकी और प्रक्रिया को आत्मसात कर लेती हैं, इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के निर्माण में विविधता लाने के प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय कंपनियां वियतनाम समेत आसियान के अन्य देशों में विनिर्माण असेंबली इकाई स्थापित करने का प्रयास कर सकती हैं। हालिया दिनों में चिकित्सा संबंधी विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में काफी रुझान देखा गया है, और यह रुझान आसियान देशों के लिए भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में दीर्घावधि साझेदारी और भारत में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के जरिए आसियान से भारत में निवेश बढ़ा है। इससे रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए बाहर जाने की आवश्यकता खत्म होगी और भारत की स्थानीय क्षमताओं के विकास में मदद मिलेगी। भारत और आसियान अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर और सामग्रियों में अनुसंधान और विकास तथा कौशल विकास तथा 5जी, स्वचालित विनिर्माण और रोबोटिक्स आदि शामिल हैं।

मोटर-वाहन और संबंधित उपकरण (ऑटोमोबाइल और ऑटो-पुर्जे)

पिछले कुछ वर्षों में आसियान ऑटोमोटिव क्षेत्र मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और इनके आपूर्तिकर्ताओं, दोनों के प्रमुख उत्पादन केंद्र और प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। इसका कारण रहा है- तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार, एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और तुलनात्मक रूप से सस्ते श्रम की

उपलब्धता। ज्यादातर वैश्विक ऑटो कंपनियों की मौजूदगी आसियान में भी है। इन्होंने क्षेत्रीय उत्पादन रणनीति अपनाई है। इसके बाजूद, इन उत्पादक देशों में ऑटो पुर्जे अब भी बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। इस तरह भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए इसमें अच्छे अवसर हैं। आसियान देशों में ऑटोमोबाइल उद्योग के बढ़ने से भारतीय विनिर्माताओं और ऑटोमोबाइल पुर्जों के वितरकों के लिए आसियान में निवेश के व्यापक अवसर हैं। कई आसियान देश प्राकृतिक रबड़ के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। ऐसे में टायर विनिर्माताओं के लिए भी वहां कई अवसर मौजूद हैं ।

आसियान देश डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण कौशल में भारत की सापेक्ष स्पर्धात्मकता का लाभ उठा सकेंगे। भारत में चार पहिया और दो पहिया वाहनों का बहुत बड़ा बाजार है। हालांकि ड्राइव ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इंटीरियर्स, इंजन कंपोनेंट्स और अलॉय व्हील्स जैसे कुछ ऑटो पुर्जों के आयात के लिए भारत, चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि आरवीसी में एकीकरण के जरिए भारत द्वारा इन उपकरणों का स्थानीय स्तर पर विनिर्माण कर आसियान अर्थव्यवस्थाओं को भेजा जा सकता है।

आसियान के उपकरण विनिर्माताओं और डिजाइनरों के साथ संयुक्त उद्यमों और तकनीकी गठजोड़ के जरिए भारत को कम समय में उन्नत प्रौद्योगिकियों को यहां लाने में मदद मिल सकती है। जबकि लंबे समय में इससे हमारे आंतरिक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने और इसके जरिए स्थानीय स्तर पर तकनीक को और विकसित करने की भारत की योजना में भी लाभ मिल सकता है। इस तरह स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित हो सकती है। भारत और आसियान देश इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ निकेल उत्पादन के कारखानों की स्थापना करने पर भी विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उत्पाद

भारत और आसियान देश, अपनी बढ़ती बुजुर्ग आबादी और गैर-संक्रामक, क्रोनिक और जीवनशैली जनित बीमारियों सहित, स्वास्थ्य संबंधी एक जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सेवा संबंधी खर्च भी बढ़ रहा है। क्षमता विकास और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के जरिए भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ने से वर्तमान में, विशेष रूप से कोविड-19 की परिस्थितियों में इस क्षेत्र ने नई महत्ता हासिल की है।

कई आसियान देशों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का स्थानीय उत्पादन उनकी घरेलू मांग की आपूर्ति की तुलना में कम है। जैसे 'म्यांमार फार्मासूटिकल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज' के अनुसार, 2018 में, देश में स्थानीय उत्पादन से घरेलू मांग की केवल 10% ही आपूर्ति हो पाई थी। जबकि भारत दुनिया में जेनरिक दवाओं का अग्रणी उत्पादक है। आसियान कंपनियां अपनी एपीआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन और भारत दोनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। तदनुसार, आसियान और भारत के बीच बहुराष्ट्रीय जीवन विज्ञान कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से इस क्षेत्र में एपीआई अवयवों का उत्पादन करने के लिए निवेश और सहयोगात्मक अवसर मौजूद हैं।

भारत अपने मजबूत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों और सस्ती तथा गुणवत्ता वाली दवाओं के साथ आसियान देशों के स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत कम लागत पर चिकित्सा उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए आसियान का सहयोग कर सकता है। साथ ही टीके, एंटीबायोटिक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों सहित आवश्यक चिकित्सा उत्पादों का और अधिक उत्पादन करने के लिए क्षमता विकास कर सकता है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों, सस्ती व गुणवत्ता वाली दवाओं (पारंपरिक और पूरक दवाओं) जैसे क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सकता है, जिनमें भारत मजबूत स्थिति में है। वहीं भारत भी थाइलैंड जैसे आसियान देशों में सफल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना से काफी कुछ सीख सकता है। साथ ही ई-परामर्श और टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में आसियान कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकता है।

कृषि व्यापार और खाद्य प्रसंस्करण

भारत और आसियान मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है। आसियान देश अपने प्राकृतिक संसाधनों, खासकर कृषि उत्पादों के कारण निर्यात उद्योगों के विकास में सफल रहे हैं। इन विकासक्रमों के बावजूद, आसियान के पास जैविक उत्पादन के लिए जैव आदानों की अनुपलब्धता, असंगत आपूर्ति, उच्च उत्पादन लागत और किसानों की क्षमता के साथ-साथ प्रसंस्करण स्तर की समस्याएं जैसी अन्य चुनौतियों के अलावा एक चुनौती यह भी है कि यहां कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। अपनी सीमाओं को समझते हुए आसियान अर्थव्यवस्थाएं संपोषी जैविक मूल्य श्रृंखलाओं के जरिए कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रयास कर रही हैं।

भारतीय कंपनियां आसियान के कई देशों में निजी क्षेत्रों को सहयोग दे सकती हैं और तकनीकी जानकारी के साथ-साथ बाजार संबंधी (खरीद-फरोख्त) सेवाओं के मामले में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकती हैं। कृषि और खाद्य उत्पादों में एक-दूसरे की पूरकता को देखते हुए, भारत और आसियान देश अपने तुलनात्मक लाभों को और बढ़ाने के लिए अपने कृषि उत्पादों की परस्पर आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते कृषि आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है तथा भारत और आसियान देशों में सुदृढ़ कृषि आपूर्ति श्रृंखला तंत्र तैयार करने के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। इसके लिए कच्चे माल, उत्पादन, कटाई, भंडारण, बुनियादी ढांचे, रसद, मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृषि वित्त सहित कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग और मिलकर काम करने की आवश्यकता है। गैर-खाद्य कृषि उत्पादों (तंबाकू, रबड़, लकड़ी) का प्रसंस्करण एक अन्य क्षेत्र है, जिसमें भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आरवीसी का विस्तार करने और जीवीसी का एक प्रमुख हिस्सा बनने के लिए भारत और आसियान अर्थव्यवस्थाओं के बीच रणनीतिक योजना बनाई जाए तो दोनों के कृषि क्षेत्र को उन्नत किया जा सकता है।

इस प्रकार, भारत और आसियान देशों में आपूर्ति श्रृंखला बनाने के पीछे मूल विचार यह है कि प्रत्येक देश उत्पादन के विभिन्न चरणों में तुलनात्मक लाभ का अधिकतम उपयोग करेगा। जीवीसी में अपने आप को रणनीतिक रूप से जगह देकर आसियान देश और भारत, अपने लोगों की विदेशी मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के साथ-साथ एशियाई क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन प्रक्रियाओं में मूल्यवर्धन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ■

भारत से कृषि निर्यात को बढ़ाना

वर्ष 2019 के दौरान भारत से कृषि कमोडिटीज़[1] का निर्यात 34.8 बिलियन यूएस डॉलर का आंका गया। वर्ष 2010 से 2019 के दौरान भारत के समग्र निर्यातों में 4.3% की सीएजीआर की तुलना में कृषि कमोडिटीज़ के निर्यात में 6.8% की सीएजीआर दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर, 2019 के दौरान कृषि कमोडिटीज़ के शीर्ष निर्यातकों में भारत 14वें स्थान पर रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान 6.7 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों के साथ भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात सर्वाधिक रहा। इसके बाद करीब 4.4 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों के साथ बासमती चावल का दूसरा स्थान रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात किए गए अन्य प्रमुख कमोडिटी समूहों में मसाले, मांस से बने पदार्थ, चीनी और गुड़ तथा गैर-बासमती चावल आदि शामिल रहे।

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से निर्यात किए गए कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए यूएसए सबसे बड़ा आयातक रहा। यूएसए को 4.6 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। वर्ष के दौरान चीन को 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य प्रमुख आयातक ईरान, वियतनाम, यूएई तथा सऊदी अरब रहे।

भारत की कृषि नीतियां

भारत में कृषि व्यापार नीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने, आयात निर्भरता को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न सहायता कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वित किए गए हैं, जो उत्पाद एवं गैर-उत्पाद दोनों प्रकार के हैं।

सरकार ने कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) तैयार की थी। इस नीति का मूल उद्देश्य "उपयुक्त नीति के जरिए भारतीय कृषि निर्यात क्षमता का दोहन करना, कृषि क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली देश बनाना तथा किसानों की आय को बढ़ाना है।"

उक्त कृषि निर्यात नीति का फोकस ऐसा स्थिर नीतिगत परिवेश बनाने पर है, जिससे संसाधनों का सदुपयोग करते हुए बाजार की मांग के अनुरूप बेहतर उत्पाद बनाए जाएं, जिनके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्चतर दाम मिलें। कृषि निर्यात नीति में नवगठित लॉजिस्टिक डिवीजन के जरिए कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली लॉजिस्टिकल बाधाओं के निवारण के उपाय सुझाए गए हैं। साथ ही, एईपी के हिस्से के रूप में, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उत्पाद-जिला क्लस्टरों को चिह्नित किया गया है।

भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग चक्र में 2016-20 की अवधि के लिए ₹ 6000 करोड़ के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना) नामक एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए सरकार ने खेत से खुदरा दुकानों तक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की है।

किसानों को समय पर ऋण सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना बनाई गई है। केसीसी कार्डधारक किसानों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सामान्य ऋणों की उच्च ब्याज दरों से मुक्ति मिल जाती है। केसीसी ब्याज दर न्यूनतम 2% से लेकर औसतन 4% के बीच होती है। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने मत्स्यपालन क्षेत्र में भी केसीसी सुविधा प्रदान की है।

भारत सरकार 2020 में 3 नए कृषि कानून लाई, जिनमें (i) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक (संवर्धन और सरलीकरण), 2020; (ii) कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020; तथा (iii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश और किसानों की आय बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अलावा, सरकार उत्पादन के लिए सामग्री एवं संसाधनों के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने हाल ही में वैश्विक खाद्य पदार्थों के विनिर्माण चैंपियन बनाने के क्रम में सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (PLISFPI) हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना आरंभ की है।

कृषि क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने एवं सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलें की गई हैं। सरकार ने किसानों के लिए फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ₹ 1 लाख करोड़ की कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि निर्धारित की है। इसके अलावा, सरकार ने ₹ 15,000 करोड़ की पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (AHIDF) की व्यवस्था की है; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के विकास के लिए ₹ 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की है; तथा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए ₹ 10,000 करोड़ की योजना तैयार की है।

केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई निधि की ₹ 5,000 करोड़ की प्रारम्भिक राशि को बढ़ाकर दोगुना करने का सुझाव दिया है। उक्त योजना के तहत ऋणों की मंजूरी के लिए ₹ 3,970.17 करोड़ की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है।

भारत सरकार, आरबीआई, नाबार्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न पहलों के चलते कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंकों ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को ₹ 13.68

[1] एचएस 01 से एचएस 24

लाख करोड़ की ऋण सहायता राशि संवितरित की, जो गत वर्ष प्रदान की गई ऋण सहायता राशि से लगभग 8.80% अधिक रही। इंडिया एक्ज़िम बैंक विभिन्न उद्योगों को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर इंडिया एक्ज़िम बैंक का कुल ऋण एक्सपोजर ₹ 1,263.03 करोड़[2] (लगभग 173.4 मिलियन यूएस डॉलर) रहा, जो समग्र उद्योगों पर कुल ऋण एक्सपोजर का 1.8% है।

भारत के कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए रणनीतियां

इस अध्ययन में कुछ ऐसी रणनीतियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें भारत के कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपनाया जा सकता है। अधिकाधिक कृषि निर्यातों के लिए अपनाई जा सकने वाली कुछ प्रमुख रणनीतियां नीचे दी गई हैं:

उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना: निर्यातित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उन्हें अधिक समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसानों को निर्यात योग्य किस्मों, नई उत्पादन तकनीकी, फसल कटाई और फसल कटाई पश्चात प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए भावी उत्पादों की गुणवता के लिए निर्यात बाजार की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने की जरूरत है।

तकनीकी सहयोग तथा अनुसंधान एवं विकास: इसमें भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भूमि का भू-मानचित्रण, किसानों एवं कृषि उत्पादक संघों (एफपीओ) का पंजीकरण; उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पूरे कोल्ड स्टोरेज एवं संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना; कृषि मशीनीकरण को बढ़ाना; फसल कटाई प्रबंधन; आयोजना में कृत्रिम बुद्धिमता को लागू करना; निगरानी; फसल कटाई एवं आवंटित संसाधन शामिल हैं। नए उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) जरूरी है। हालांकि उत्पाद एवं कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ अनुपालन सुनिश्चित करना: न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नीतियों को भी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप बनाना होगा। भारत को अपना फोकस घरेलू सब्सिडी से हटाकर प्रत्यक्ष आय सहायता पर करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ कृषि करार के अनुसार, किसानों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष भुगतान ग्रीन बॉक्स के तहत आते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष सहायता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष सहायता में अन्य के साथ-साथ आय की गारंटी तथा सुरक्षा कार्यक्रम; संरचना समायोजन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम; तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

बाजार की जानकारी: विभिन्न देशों में व्यापार अवसरों और व्यवसाय परिवेश संबन्धित व्यापक जानकारी मुहैया कराने के लिए एक सूचना प्लैटफॉर्म बनाया जा सकता है। संभावित बाज़ारों की तलाश करते समय विशिष्ट उपभोक्ता रुचियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों में वैज्ञानिक तरीके से निरंतर सुधार लाने की आवश्यकता है।

बाजार पहुंच को बढ़ाना: भारत में आयातों के साथ-साथ निर्यातों के लिए बाजार पहुंच अनुरोधों को डील करने और कृषि क्षेत्र से संबन्धित सभी प्रकार के सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी मसलों को देखने के लिए एक एकीकृत निकाय गठित करने की भी जरूरत है। किसी भी द्विपक्षीय व्यापार चर्चा के अंतर्गत भारत को सवा अरब की आबादी वाले अपने विशाल बाजार का लाभ उठाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: किसी सफल कृषि निर्यात नीति के लिए अंतिम उपभोक्ता तक संपर्क श्रृंखला स्थापित करना एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। किसी देश के निर्यातों को बढ़ाने में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा प्रसंस्करण सुविधाओं, अच्छी सड़कों, फसल कटाई के उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं एवं बन्दरगाहों पर विश्व स्तरीय निकास व्यवस्था की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण रही है। कृषि मूल्य श्रृंखला में सुदृढ़ बैकवर्ड लिंकेज सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को भी शामिल किया जाना चाहिए।

पीपीपी मॉडल को अपनाना: सख्त पूरकता परिवेश में पीपीपी मॉडल इस क्षेत्र में कई स्तरों पर बदलाव ला सकता है। निजी निवेश के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में सरकार की अहम भूमिका होगी।

ब्रांड इंडिया बनाना: "ब्रांड इंडिया" की मार्केटिंग और प्रचार ऐसी पहल है, जिससे नए विदेशी बाजारों एवं नए उत्पादों में अपनी पहुंच बनाकर भारत के निर्यातों को और बढ़ाया जा सकता है। इससे स्वतः ही उच्चतर मूल्य अर्जन होगा। मूल्ययोजित और आदिवासी समुदायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय प्लैटफॉर्मों पर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कौशल विकास: मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए कुशल श्रमशक्ति का होना बहुत जरूरी है। मशीनीकरण में वृद्धि, आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा कृषि प्रबंधन में प्रौद्योगिकी को अपनाना और मूल्य श्रृंखला विकास से संपूर्ण कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षमता निर्माण की जरूरत होगी। इसके लिए उद्योग और बाजार की मांग के अनुरूप कौशल विकास और क्षमता निर्माण में उल्लेखनीय स्तर पर निरंतर निवेश की जरूरत है।

संस्थागत कृषि ऋण संवितरण को सुदृढ़ करना: कृषि गतिविधियों और खेती पर निर्भर परिवारों वित्तीय समावेशन के लिए उन्हें संस्थागत कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने और तकनीक आधारित समाधान अपनाने की दिशा में तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। इसके साथ ही किसानों को एकीकृत, समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को कृषि-तकनीकी कंपनियों/ नवोद्यमों के साथ मिलकर काम करने के विकल्प तलाशने की जरूरत है।

पर्यावरण अनुकूलन: उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, जैविक कृषि को बढ़ावा देने, हरी खाद, जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों के उत्पादकों को सब्सिडी देने तथा शहरी ठोस कचरों के उपयोग से बड़े पैमाने पर खाद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा सकती हैं।

विभिन्न सरकारी योजनाओं का संयोजन: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की निर्यात संवर्धन योजना को एक एकीकृत योजना के रूप में अपनाया जाना चाहिए तथा सूचनाओं तक किसानों और निर्यातकों की पहुंच और समझ को आसान बनाने के लिए इसे एक प्लैटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ■

[2] यथा मार्च 2021 को

भारत-बांग्लादेश साझेदारी को सुदृढ़ बनाना

बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। 2015 से 2019 के दौरान औसतन 7.4% की सुदृढ़ वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। हालांकि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, 2020 में इसकी वृद्धि में 3.8% तक की गिरावट आई। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, जिसकी समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। जनसंख्या एवं आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश सबसे कम विकसित (एलडीसी) देश है। वर्ष 2019 में 166.6 मिलियन जनसंख्या के साथ विश्व का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश भी यही रहा।

भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो इन्हें रणनीतिक साझेदारी से भी आगे ले जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश भारत की सीमा से तीन ओर से घिरा हुआ है। दोनों देशों के बीच 4,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा लगती है। वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), एशिया-प्रशांत व्यापार करार (APTA) तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रिम संघ (आईओआर-एआरसी) के सदस्य हैं। बड़ी संख्या में निर्यात वस्तुओं के लिए बांग्लादेश को भारत से सार्क तरजीही व्यापार समझौता (साप्टा) वार्ताओं के तहत तथा साफ्टा के व्यापार उदारीकरण योजना के हिस्से के रूप में भी भारत से बाजार पहुंच के लिए वरीयता प्राप्त है। इन समझौतों के तहत भारत बांग्लादेश को तरजीही बाजार पहुंच और एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान्य (डीएफटीपी) योजना मुहैया कराता है। इससे बांग्लादेश को भारत की कुल टैरिफ लाइन के लगभग 98% हिस्से तक शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलती है।

वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश, भारत से निर्यातित उत्पादों के 5वें सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है। भारत के कुल निर्यात का 3% बांग्लादेश को निर्यात किया गया। वर्ष 2010-11 में कुल निर्यातों की 1.2% हिस्सेदारी के साथ यह 21वां सबसे बड़ा आयातक रहा। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 2020-21 के दौरान इस देश में भारत का कुल निर्यात 42.5% तथा इस देश से भारत का कुल आयात 32.3% रहा। वर्ष 2010-11 से 2020-21 के दौरान भारत से बांग्लादेश के निर्यातों में 11.7% की उल्लेखनीय एएजीआर दर्ज की गई तथा निर्यात 2010-11 के 3.8% बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 9.1 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। बांग्लादेश से आयात भी 2010-11 के 0.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। इसमें 11.3% की एएजीआर दर्ज की गई। (चार्ट 1)।

चार्ट 1: बांग्लादेश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार

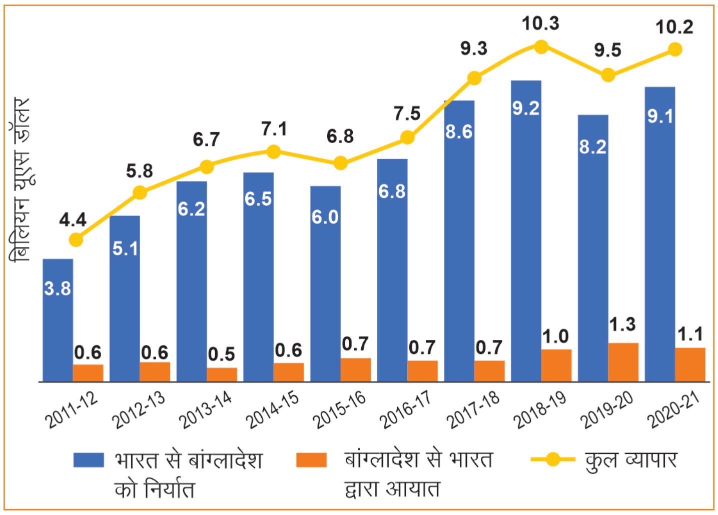

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा इंडिया एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

वर्ष 2020-21 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत के निर्यात विविधतापूर्ण रहे। भारत से बांग्लादेश को कपास (19.5%), खनिज ईंधन (11.2%), अनाज (9.8%), वाहन (7.5%) तथा मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण क्रमशः (6.1%) का निर्यात किया गया। इस अवधि के दौरान बांग्लादेश से भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं बिना बुने या सिले कपड़े (16.8%), पशु तथा वनस्पति वसा एवं तेल (13.9%), बुने और सिले सिलाए कपड़े (10.7%), कपड़ों से तैयार अन्य सामान (9.6%) तथा प्राकृतिक टेक्सटाइल फाइबर (9.2%) शामिल रहे।

भारत बांग्लादेश के लिए भी महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार है। वर्ष 2020 के दौरान भारत बांग्लादेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा। कुल वैश्विक आयातों का 17% बांग्लादेश द्वारा किया गया तथा यह 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। कुल वैश्विक निर्यात का 2.5% बांग्लादेश को रहा। इसके बावजूद विद्यमान गैर-टैरिफ बाधाओं, जटिल प्रक्रियाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर बाधाओं के कारण दोनों देश पूरी तरह से व्यापार क्षमता का दोहन कर पाने में असमर्थ हैं। यदि व्यापक आर्थिक समझौता, जिस पर वर्तमान में वार्ता जारी है, कामयाब होता है तो अप्रयुक्त व्यापार और निवेश क्षमताओं का दोहन किया जा सकता है।

अप्रैल 1996 से मार्च 2021 के दौरान, इक्विटी, ऋण और जारी गारंटियों सहित बांग्लादेश में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारत का मंजूर एफडीआई (जावक एफडीआई) 527.2 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। निवेश किए गए प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, थोक, फुटकर व्यापार तथा रेस्त्रां एवं होटल, विद्युत, गैस तथा जल; वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यवसाय सेवाए (चार्ट 2) आदि शामिल हैं। कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में निवेश किया है, जिनमें मैरिको, इमामी,

डाबर, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, गोदरेज, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प आदि शामिल हैं।

चार्ट 2 : बांग्लादेश में क्षेत्रवार भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

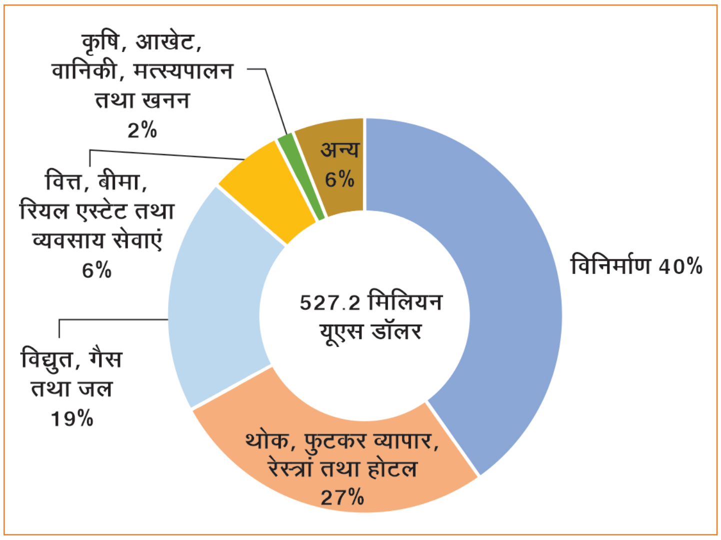

बांग्लादेश में अप्रैल 2010 से मार्च 2020 के दौरान अनुमोदित अन्य संचयी निवेश मदों में सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जल, थोक, फुटकर व्यापार, रेस्त्रां एवं होटल तथा परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं शामिल रहीं, जिनमें 527.2 मिलियन यूएस डॉलर का संचयी निवेश रहा।

स्रोतः आरबीआई और इंडिया एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

बांग्लादेश बैंक के अनुसार, भारत 2019 के दौरान 725 मिलियन यूएस डॉलर के निवेश के साथ बांग्लादेश में 10वां सबसे बड़ा निवेशक रहा, जिसने मुख्य रूप से दूरसंचार (20.8%), उसके बाद बैंकिंग (18.1%), वस्त्र एवं परिधान (13.7%), बिजली (8.5%) तथा रसायन एवं फार्मासूटिकल (4%), व्यापार (3.7%), कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (3.4%) तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं आईटी (1%) के क्षेत्र में निवेश किया। वहीं दूसरी ओर, अप्रैल 2000 से मार्च 2021 के दौरान भारत में बांग्लादेश का संचयी आवक निवेश 0.1 मिलियन यूएस डॉलर का रहा।

अपने मध्यम एवं दीर्घावधि सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए बांग्लादेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास लंबे समय से आवश्यक रहा है। बांग्लादेश की 2021-41 की परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, यहां वर्ष 2041 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता प्रतिवर्ष 10 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत, परिवहन में निवेश एक गुणक के रूप में कार्य कर सकता है तथा परिचालन लागत को कम कर, समय की बचत कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय कॉरिडोर के निर्माण से इसे और आगे बढ़ाने से वैश्विक क्षेत्र में पूर्वी उपमहाद्वीप के महत्त्व को फिर से बढ़ाया जा सकेगा। यह भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। विश्व बैंक के हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच निर्बाध परिवहन कनेक्टिविटी से दोनों देशों की राष्ट्रीय आय क्रमशः 7.6% तथा 16.6% बढ़ सकती है। बांग्लादेश बिम्सटेक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) के साथ-साथ विशेष रूप से भारत के लिए संपर्क सूत्र है। अतः कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पूर्वोत्तर भारत के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ भारत के एक्ट ईस्ट विजन का विस्तार करने में भी सहायक होगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती आर्थिक भागीदारी दोनों देशों के बीच विद्युत क्षेत्र में साझेदारी में स्पष्ट परिलक्षित होती है। इन दोनों देशों के बीच सड़क और रेल परिवहन को सुगम बनाने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए अभी तक पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका है। बांग्लादेश की 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हालांकि सड़क और पुलों के मामले में इन्फ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय विकास हुआ है, लेकिन जल परिवहन क्षेत्र में निवेश थोड़ा कम हुआ है। भारत द्वारा हाल ही में घोषित मैरीटाइम विजन 2030 का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए पूर्वी जलमार्ग कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड (EWaCTG) को विकसित करना है। परिवहन का सबसे प्रभावी तथा पर्यावरण अनुकूल साधन जलमार्ग रहा है।

द्विपक्षीय कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए मई 2020 में मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 करने के लिए अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करने जैसी हालिया पहलों से निश्चित ही दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जलमार्गों को जोड़ने में सहायता मिलेगी। इससे अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, जहाजों तथा आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति तथा इन मार्गों के कामकाज में तेजी लाने के लिए ड्रेजिंग कार्यों में सहयोग बढ़ेगा।

भारत ने औद्योगिक गतिविधियों में निवेश के लिए मोंगला (मोंगला पोर्ट के पास), कुश्तिया (भारतीय सीमा पर एक जिला) तथा मीरसराय (चटगांव जिले) के आर्थिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित की है। अंतर्देशीय जलमार्गों को आर्थिक क्षेत्रों और बंदरगाहों से इस प्रकार जोड़ने के लिए भारत सड़क और रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है जिससे मल्टीमॉडल परिवहन व्यवस्था काम कर सके।

मार्च 2021 में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान, दोनों देश "क्षेत्र और विश्व में साझेदार के रूप में" साथ काम करते रहने और बीबीआईएन मोटर वाहन करार को परिचालन में लाने के लिए बिम्सटेक को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु इसे सुगम बनाने के लिए इसमें प्राथमिकता के आधार पर सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। व्यापार बढ़ाने और भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों / भू-बंदरगाहों के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के उन्नयन के लिए कनेक्टिविटी मुख्य पहलू रहा है।

भारत और बांग्लादेश को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को एकीकृत करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने और क्षेत्रीय सहयोग पहलों में निहित संभाव्यता का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अतः, व्यापार के लिए अतिरिक्त कॉरिडोर बनाना और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अधिकाधिक सहयोग करना जरूरी है, जिससे महामारी की वजह से आई बाधाओं को दूर किया जा सके और सुदृढ़ साझेदारी के जरिए स्थिर वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। ■

भारतीय परिधान उद्योग

भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्य की दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन में इसका 7%, भारत के GDP में 2% तथा देश की निर्यात आय में लगभग 10.8% योगदान रहता है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक तथा संबद्ध क्षेत्रों में 60 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण लोग शामिल हैं।

भारतीय रेडीमेड वस्त्र / परिधान उद्योग, भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग के कुल के लगभग 50% हिस्से के साथ इस उद्योग का सबसे बड़ा खंड है। उद्योगों के वार्षिक सर्वे 2017-18 के अनुसार, 10,498 कारखानों में परिधान बनाए जा रहे थे। हालांकि भारतीय परिधान क्षेत्र विशेष रूप से असंगठित है और खंडों में विभाजित है। बड़ी संख्या में छोटे विनिर्माताओं के होने के कारण परिधान उद्योग औपचारिक आकार नहीं ले पा रहा है। अधिकांश उत्पादन छोटे-छोटे क्लस्टरों द्वारा किए जाते हैं और ये क्लस्टर अन्य के साथ-साथ बेंगलूरु, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई तथा तिरुपुर जैसे शहरों में हैं। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में कुल परिधान उत्पादन का 95% शीर्ष 19 क्लस्टरों द्वारा किया जाता है।

वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2019 के दौरान वैश्विक बाजार में 898.3 बिलियन यूएस डॉलर के परिधान तैयार किए गए। परिधान विनिर्माण बाजार में 2015 से 2019 के दौरान 5.3% की सीएजीआर दर्ज की गई। 2019 के दौरान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कुल परिधान उत्पादन का लगभग 64% उत्पादन किया गया। यूरोपीय क्षेत्र में बाजार की हिस्सेदारी लगभग 30% रही। वर्ष 2019 के दौरान वैश्विक परिधान बाजार के राजस्व में पश्चिमी यूरोप, चीन, यूएसए तथा भारत शीर्ष योगदानकर्ता रहे।

वर्ष 2019 में वैश्विक परिधान निर्यात 475.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 0.1% की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2019 में 138.2 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों के साथ चीन परिधानों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा और वैश्विक परिधान निर्यातों में इसकी 29.1% की हिस्सेदारी रही। 2019 में चीन के बाद परिधान निर्यातों में बांग्लादेश की वैश्विक हिस्सेदारी 8.5% रही। 2019 में अन्य प्रमुख परिधान निर्यातकों में वियतनाम (वैश्विक परिधान निर्यातों का 7.0%), जर्मनी (5.0%), इटली (5.0%), भारत (3.4%) तथा तुर्की (3.3%) का स्थान है।

भारतीय परिदृश्य

भारत परिधान का निवल निर्यातक है, जिसका 2019 में 15.4 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा। वर्ष 2019 में भारत से परिधानों का निर्यात 16.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें गत वर्ष की 15.7 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दशक के दौरान निर्यातों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2019 के दौरान भारत से परिधान निर्यातों में 5% की सीएजीआर दर्ज की गई, जिसमें 2017 में निर्यात शीर्ष पर पहुंचकर 17.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया था।

चार्ट 3: भारत से परिधान निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर में)

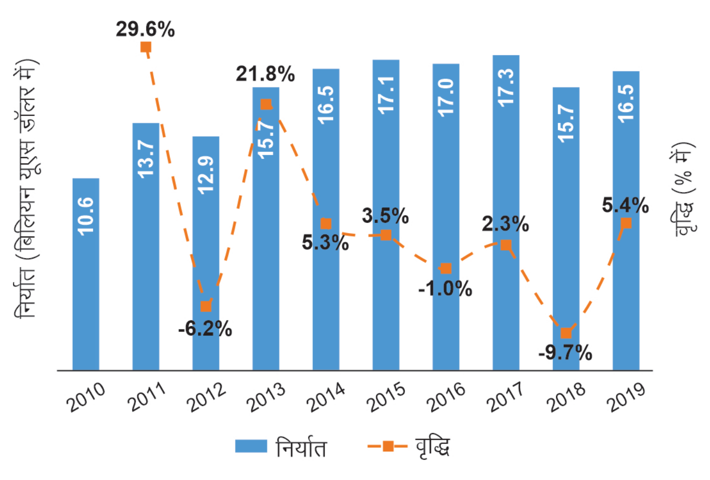

स्रोतः डाटा आईटीसी ट्रेड मैप, अक्टूबर 2020, से लिया गया; इंडिया एक्ज़िम बैंक शोध

परिधानों में सबसे ज्यादा निर्यात की गई वस्तुओं में एसेसरीज़ सहित सूती कपड़े शामिल रहे। 2019-20 में इनका 8.6 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया। इसके बाद, 2019-20 में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों के साथ मानव निर्मित फाइबर से बने कपड़ों का सर्वाधिक निर्यात रहा।

आयातकों की बात की जाए तो 2019 में कुल परिधान निर्यात का 59.1% आयात शीर्ष पाँच देशों द्वारा किया गया, जो उल्लेखनीय बाजार संकेंद्रण को दर्शाता है। भारत से परिधानों का सबसे ज्यादा निर्यात यूएस को किया जाता है। 2019 में 4.4 बिलियन यूएस डॉलर का परिधान निर्यात किया गया, जो भारत से किए गए कुल परिधान निर्यातों का 26.7% है। भारत से यूएस को परिधान निर्यातों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2014 के 21.7% से बढ़ाकर 2019 में 26.7% हो गई है। अन्य प्रमुख आयातक देशों में यूएई (भारत के परिधान निर्यातों में 11.5% की हिस्सेदारी), यूके (9.7%), जर्मनी (6.4%), स्पेन (4.7%) तथा फ्रांस (4.5%) शामिल रहे।

वर्ष 2018 के दौरान, परिधान आयातों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। यह 55.1% बढ़ाकर 1.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई तथा आगामी वर्ष में भी इसमें वृद्धि जारी रहने की संभावना है। 2019 में भारत में परिधान आयात 1.14 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दशक

में, भारत द्वारा परिधान आयात में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 2010 से 2019 के दौरान 23.2% की वृद्धि दर्ज की गई है।

चार्ट 4: भारत द्वारा परिधान का आयात (मिलियन यूएस डॉलर में)

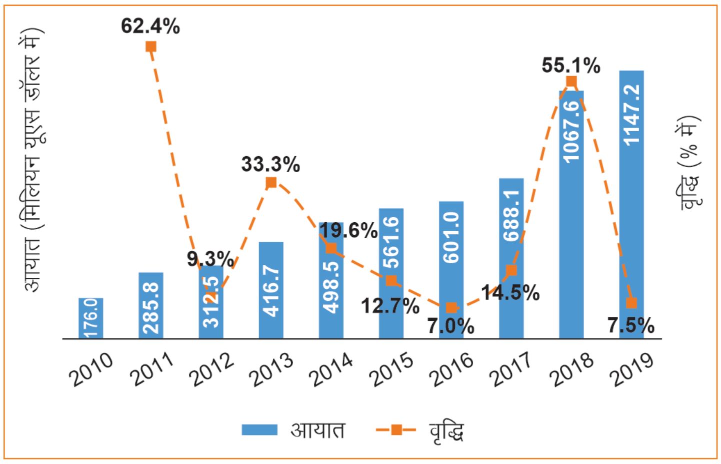

स्रोतः डाटा आईटीसी ट्रेड मैप, अक्टूबर 2020, से लिया गया; इंडिया एक्ज़िम बैंक शोध

भारत को वस्त्र निर्यातक देशों की बात की जाए तो, 2019 में भारत द्वारा किए गए कुल वस्त्र आयातों का 81.6% का आयात शीर्ष पाँच देशों से किया गया। इसमें भी 61.5% का आयात शीर्ष दो देशों से रहा। भारत को परिधानों का सबसे बड़ा निर्यातक बांग्लादेश है। 2019 में बांग्लादेश से परिधान आयात 389.6 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो भारत द्वारा कुल परिधान आयात का लगभग 34% है। बांग्लादेश से भारत द्वारा परिधानों के आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2010 से 2019 के दौरान इसमें 42.5% की सीएजीआर दर्ज की गई, जो भारत द्वारा समग्र परिधान आयात के सीएजीआर से काफी ज्यादा है। बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। 2019 में भारत द्वारा किए गए परिधान आयातों में इसकी हिस्सेदारी 27.5% रही। 2010 से 2019 के दौरान भारत द्वारा चीन से किए गए परिधान आयात में 20.2% की सीएजीआर दर्ज की गई। भारत के लिए अन्य प्रमुख निर्यातकों में स्पेन (भारत के परिधान आयात में 8.5% की हिस्सेदारी), श्रीलंका (5.8%), हांगकांग (5.8%) तथा वियतनाम (3.5%) शामिल रहे।

भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र में 2019 में एफडीआई इक्विटी आवक 319.9 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के दौरान इस क्षेत्र में 3,464.1 मिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई रहा, जो इस अवधि के दौरान समग्र एफडीआई इक्विटी आवक का 0.7% था।

सरकारी पहलें

भारत सरकार ने दीर्घावधि में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 100% एफडीआई के साथ अगले कुछ वर्षों में 140 बिलियन यूएस डॉलर (₹10,485 बिलियन) के विदेशी निवेश की उम्मीद है। इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक निजी इक्विटी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय निवेश चिह्नित किए हैं। भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग के विकास में और तेजी लाने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के विकास एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सात राज्यों में रेडीमेड कपड़ों के लिए 21 विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ₹ 6,900 मिलियन (106.58 मिलियन यूएस डॉलर) की राशि आवंटित की है। भारत सरकार ने एमएमएफ तथा टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। इसके लिए पांच वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 10,683 करोड़ के वित्तीय व्यय को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में ब्राउनफील्ड निवेश के लिए एक वर्ष की उत्पादन पूर्व अवधि और ग्रीनफील्ड निवेश के लिए दो वर्ष की उत्पादन पूर्व अवधि के बाद निर्धारित टर्नओवर पर पांच वर्षों के लिए 3% से 15% तक का वृद्धिशील प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

महामारी से संबंधित व्यवधान

कोविड-19 महामारी का व्यापक प्रभाव लगभग सभी विनिर्माण क्षेत्रों पर पड़ा है। वैश्विक तथा राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वस्त्र एवं परिधान उद्योग प्रभावित हुआ है। खुदरा क्षेत्र में कोविड-19 से पूर्व के आकलन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में खुदरा परिधान में लगभग 27 बिलियन यूएस डॉलर (₹ 2,042 बिलियन) की गिरावट आने की आशंका है। 2020 में भारत से परिधान निर्यातों में -24.7% की वर्ष-दर-वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई और कुल निर्यात 12.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के बाद वस्त्र एवं परिधान उद्योग में अपेक्षाकृत रूप से कमी आने की संभावना है और 2024 तक यह बाजार 120 बिलियन यूएस डॉलर (₹ 9,074 बिलियन) का आंका गया है।

हालांकि भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए प्रयासरत है। अतः इस उद्योग को आगे बढ़ाते हुए अपने सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को निभाते रहना जरूरी होगा। गारमेंट क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी दर्ज की गई है तथा महामारी की वजह से इसमें और वृद्धि का रुझान है। इसके लिए भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को अधिक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

महामारी से संबंधित व्यवधानों के बावजूद इस क्षेत्र में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पीपीई विनिर्माता के रूप में उभरा है। वर्तमान में, भारत में 600 से अधिक कंपनियां पीपीई उत्पादन के लिए प्रमाणित हैं। वर्ष 2019 के 52.7 बिलियन यूएस डॉलर (₹ 3,971 बिलियन) की तुलना में 2025 के अंत तक पीपीई का वैश्विक बाजार 92.5 बिलियन यूएस डॉलर (₹ 6,927 बिलियन) से अधिक का होने की उम्मीद है। इससे इस क्षेत्र में अधिकाधिक मांग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के जीवीसी एकीकरण को सुगम बनाने के लिए नीतिगत माध्यम के रूप में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

आज लगभग 70% अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) से होता है, क्योंकि कच्चे माल, पार्ट्स और पुर्जों का प्रायः कई बार सीमा पार आदान-प्रदान होता है। ऐसे समय में जब व्यापार में तनाव के चलते वैश्विक व्यापार भावनाएं पहले ही कम हो गई थीं, कोविड-19 महामारी से और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बड़ा झटका लगा। परिणामस्वरूप, अनिश्चितता पहले से और ज्यादा बढ़ गई। नतीजतन, कई कंपनियां अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए प्रयासरत हैं और अपनी उत्पादन मूल्य श्रृंखला में एक बड़े आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को कम करने का तंत्र विकसित कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने जोखिमों को कम करने के लिए वैकल्पिक निवेश स्थानों पर विचार कर रही हैं। इससे भारत जैसे देशों के लिए मूल्य श्रृंखला में आए नए बदलावों का लाभ उठाने के नई राहें खुल गई हैं।

मलेशिया और वियतनाम जैसी कई अर्थव्यवस्थाएं इस तरह के निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं। हालांकि, महामारी के चलते हुई तालाबंदी और आपूर्ति श्रृंखला में आए अवरोधों के कारण, वैश्विक निवेशक भी अपने निवेश संबंधी निर्णय लेते समय स्थानीय बाजार के आकार पर विचार कर रहे हैं। यह भारत के लिए अच्छा होगा क्योंकि भारत की प्रतिस्पर्धी ताकत उसके बड़े घरेलू बाजार में ही है। इसके अलावा, कम लागत वाले श्रम का आधिक्य, वस्त्रादि क्षेत्रों में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, सेवा क्षेत्र में कौशल लाभ आदि भी भारत को अन्य देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल नीतियों तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर बेहतर फोकस करने और व्यवसाय सुगमता के जरिए भारत की स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए जाते रहे हैं। व्यवसाय सुगमता के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों के चलते, विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2014 के 142वें पायदान से सुधरकर 2019 में 63वें पायदान पर आ गई है। नई क्षेत्र विशिष्ट योजना अर्थात उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, भारत को विनिर्माण निवेश केंद्र के रूप में उभरने में मदद करने के लिए उठाया गया एक और महत्त्वपूर्ण कदम है।

पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में विनिर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना से, फोकस किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश मिलने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति के बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। शुरुआती तौर पर यह योजना मोबाइल और संबद्ध उपकरणों, दवाओं व चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए लाई गई थी। किन्तु अब इसमें उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी विनिर्माण; इलेक्ट्रॉनिक्स (दूरसंचार उत्पादों, आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों सहित); ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जों; थोक में दवाओं और फार्मासूटिकल्स; चिकित्सा उपकरण; टेक्सटाइल और संबद्ध क्षेत्र (टेक्निकल टेक्सटाइल, मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित फाइबर के आरएमजी सहित); खाद्य प्रसंस्करण; सौर पीवी विनिर्माण; बिजली के बड़े सामानों (एसी, एलईडी); और स्टील उत्पादों सहित कौशल एवं प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल कर लिया गया है। चूंकि प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में से एक, भारत से मर्चैंडाइज़ निर्यात योजना 31 दिसंबर, 2020 से समाप्त कर दी गई थी। अतः निर्यातों को बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना शुरू करने का समय भी उपयुक्त है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट के लिए नई योजना के साथ पीएलआई योजना देश को अधिक व्यापक, उत्पादन उन्मुख और डब्ल्यूटीओ-अनुरूप प्रोत्साहन प्रणाली की ओर ले जाएगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और इससे इस क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

पीएलआई योजना से भारतीय विनिर्माताओं को मूल्य श्रृंखला बढ़ाने में मदद मिलने और देश से बेहतर मूल्य वर्धित निर्यातों की संभावना है। यह बात उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर सही है, जहां भारत को वर्तमान में व्यापार अधिशेष प्राप्त है। इसके अलावा, उत्पादन लागत घटने से नए ग्राहकों और बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों में भारत से निर्यात की मात्रा में सुधार होगा। इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध के मुताबिक, 2019-20 के दौरान 10 पीएलआई क्षेत्रों से संचयी निर्यात 71.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और इन क्षेत्रों में काफी अप्रयुक्त क्षमता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के अनुमान के अनुसार, इन क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने से भारत के निर्यातों में 55 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि और हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना से कई प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार घाटा न्यूनतम रहने की भी संभावना है। भारत में 10 पीएलआई क्षेत्रों में से 5 में व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। इनमें एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, सोलर पीवी विनिर्माण और बिजली के बड़े सामान शामिल हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध के अनुसार, पीएलआई योजना के जरिए इन क्षेत्रों में करीब 40.9 बिलियन यूएस डॉलर के व्यापार घाटे के संतुलित होने की संभावना है। यह कुल व्यापार घाटे का एक चौथाई से अधिक और भारत के गैर-तेल मर्चैंडाइज़ व्यापार घाटे का लगभग 56.8% है।

तथापि, यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि जीवीसी के साथ लिंकेजों के जरिए निर्यातों को बढ़ावा देने से कुछ पुर्जों और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात जरूर कम हो जाएगा। इसलिए, भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई पीएलआई योजना का फोकस अर्थव्यवस्था को बचाना नहीं, बल्कि देश में उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों का क्षेत्रीयकरण करना और विनिर्माण क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से बढ़ाना है। इसके लिए, पीएलआई योजना से भारतीय विनिर्माताओं को दीर्घावधि में जीवीसी में एकीकृत करने में मदद करेगी। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा 21 जून, 2021 तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 26.94 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 274 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अप्रैल-जून 2021 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित 2 ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

i. एस्वाटीनी सरकार (स्वाज़ीलैंड) को "एस्वाटीनी में नए संसद भवन के निर्माण" के वित्तपोषण के लिए 108.28 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई है। उपरोक्त ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से एस्वाटीनी सरकार को अब तक 176.58 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 4 (चार) ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं एस्वाटीनी सरकार (स्वाज़ीलैंड) को सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, कृषि विकास और कृषि का मशीनीकरण, आपदा प्रबंधन रिकवरी साइट के निर्माण और एस्वाटीनी में नए संसद भवन के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

ii. श्रीलंका सरकार को "सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं" के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस एलओसी करार पर हस्ताक्षर के साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सरकार को अब तक कुल1529.15 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 8 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं श्रीलंका सरकार को रक्षा उपकरणों की खरीद / आपूर्ति के लिए, रेलवे लाइन (कोलंबो-मटारा) के उन्नयन, कोलंबो से मटारा के बीच दक्षिणी रेलवे कॉरिडोर के उन्नयन के लिए, (i) ओमनथाई- पिल्लई क्षेत्र में इरकॉन द्वारा रेलवे ट्रैक बिछाने, (ii) मधु चर्च-तल्लाईमन्नार क्षेत्र में इरकॉन द्वारा रेलवे ट्रैक बिछाने, (iii) मेदावछिया-मधु रेलवे लाइन के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने, (iv) पल्लई-कंकेसंथुराई रेलवे लाइन के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने, (v) उत्तरी रेलवे लाइन के लिए सिगनलिंग और टेली कम्यूनिकेशंस प्रणाली की स्थापना, कंकेसंथुराई बंदरगाह के पुनरुद्धार और सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री सरोज खुंटिया
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टावर-1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023
फोन : (011) 24607700
ई- मेल: eximloc@eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

तंज़ानिया के टबोरा, ज़ेगा और इगुंगा टाउन में जलापूर्ति के लिए लेक विक्टोरिया पाइपलाइन के विस्तार का शुभारंभ

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार की ओर से तंज़ानिया सरकार को 268.35 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। यह ऋण-व्यवस्था तंज़ानिया के टबोरा, इगुंगा और ज़ेगा कस्बों में जलापूर्ति के लिए लेक विक्टोरिया पाइपलाइन के विस्तार के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई है। इस ऋण करार पर 19 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए और 07 अक्टूबर, 2015 से यह प्रभावी हुई। इन परियोजनाओं के तहत तंज़ानिया के टबोरा, इगुंगा और ज़ेगा कस्बों में 280 किलोमीटर की ट्रांसमिशन पाइपलाइन का निर्माण, 1200 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क और विभिन्न क्षमताओं वाले 29 जल भंडारण कुंड शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 256.87 मिलियन यूएस डॉलर है।

परियोजना का औपचारिक उद्घाटन 30 जनवरी, 2021 को तंज़ानिया के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस दौरान तंज़ानिया में भारत के उच्चायोग से उप उच्च आयुक्त एवं अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे। इस परियोजना से तंज़ानिया के टबोरा, इगुंगा और ज़ेगा कस्बों सहित आसपास के गांवों के लगभग 12 लाख निवासी लाभान्वित होंगे और उन्हें पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ■

तिमाही गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोगुना से अधिक रहा इंडिया एक्ज़िम बैंक का कर पश्चात लाभ

इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना और उप प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी और श्री एन. रमेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित अनुसार रहीं:

मानदंड (क से ञ ₹ तक करोड़ में, ट से ढ तक % में)	2019-20 में निष्पादन	2020-21 में निष्पादन	2019-20 से वृद्धि
क. ऋण पोर्टफोलियो	99,447	103,851	4.43%
ख. गैर-निधिक पोर्टफोलियो	15,869	14,229	(10.34%)
ग. ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो (A+B)	115,316	118,080	2.40%
घ. निवल निवेश	10,837	10,017	(7.57%)
ड़. कुल उधारियां	105,166	109,617	4.23%
च. कुल व्यवसाय (C+D+E)	231,319	237,714	2.76%
छ. प्रति कर्मचारी व्यवसाय	651	683	4.91%
ज. परिचालन लाभ	2,031	2,823	39.00%
झ. कर पूर्व लाभ	244	356	45.90%
ञ. कर पश्चात लाभ	124	254	104.84%
ट. निवल अनर्जक आस्तियां	1.77%	0.51%	(126 बीपीएस)
ठ. जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात	20.13%	25.89%	576 बीपीएस
ड. प्रावधान कवरेज अनुपात	88.76%	96.74%	798 बीपीएस
ढ. स्लिपेज अनुपात	1.94%	1.52%	(42 बीपीएस)

ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी): वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार की ओर से बैंक द्वारा भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात में सहयोग के लिए 2.23 बिलियन यूएस डॉलर की 20 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। भारत सरकार की ओर से दी गई इन 272 ऋण-व्यवस्थाओं के पोर्टफोलियो के अंतर्गत 26.76 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं अपनी बढ़ती पहुंच के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में 64 देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने में मददगार रही हैं।

परियोजना निर्यात: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने अपनी वाणिज्यिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 3.6 बिलियन यूएस डॉलर के 38 परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों को सहायता दी। बैंक द्वारा यह वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों में निम्नलिखित शामिल रहे: बांग्लादेश में विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाएं; ऑस्ट्रेलिया में एक सौर परियोजना और विद्युत उपकरणों का इंस्टॉलेशन; थाइलैंड में सब-स्टेशनों का निर्माण।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईए): वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 3.15 बिलियन यूएस डॉलर की 32 परियोजनाओं के लिए 2.88 बिलियन यूएस डॉलर के संवितरण किए। बैंक ने बीसी-एनईआईए के तहत कई अग्रणी भारतीय निर्यातकों की ओर से निष्पादित की जाने वाली 1.78 बिलियन यूएस डॉलर की 16 परियोजनाओं को सहयोग के लिए 1.58 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धांततः प्रतिबद्धता भी दी है।

विदेशी निवेश वित्त: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 5 कंपनियों को 2 देशों में उनके विदेशी निवेशों के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹7.21 बिलियन की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा अब तक 78 देशों में 476 कंपनियों द्वारा स्थापित 637 संयुक्त उद्यमों को वित्त प्रदान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 2.03 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। जनवरी 2021 में इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 2.25 प्रतिशत की कूपन दर पर 144ए/रेग-एस फॉर्मेट में 10 वर्ष के लिए 1 बिलियन यूएस डॉलर जुटाए। ये 10 वर्षीय यूएस डॉलर निर्गम के लिए किसी भी भारतीय संस्था द्वारा सबसे कम दर पर जुटाए गए संसाधन रहे। इस इश्यू को 3.5 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के ऑर्डर मिले और उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों से 3.5 गुना से अधिक का सब्स्क्रिप्शन मिला।

वर्ष के दौरान, बैंक ने बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से द्विपक्षीय ऋणों के जरिए भी वित्त जुटाया। बैंक द्वारा अब तक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानी येन, मैक्सिकन पेसो, ऑफशोर रेन्मिन्बी, सिंगापुर डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, स्विस फ्रैंक, तुर्की लीरा और यूएस डॉलर जैसी विभिन्न मुद्राओं में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए जा चुके हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक को बजट आवंटन के जरिए भारत सरकार से ₹13 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2021 को ₹151.59 बिलियन की चुकता पूँजी और ₹24.26 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹1,272.02 बिलियन के रहे।

रेटिंग: बैंक को मूडीज द्वारा बीएए3 (ऋणात्मक); एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी-(स्थिर); फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी-(ऋणात्मक) रेटिंग तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+(स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी रेटिंग रेटिंग निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की हैं और संप्रभु रेटिंग के समान हैं। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

फ्रांस

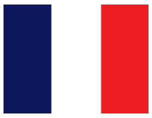

वर्ष 2020 में 8.2% की गिरावट का सामना करने वाली फ्रांस की अर्थव्यवस्था 2021 में 5.4% की वृद्धि के साथ आंशिक रूप से सुधार की ओर अग्रसर है। हालांकि इसकी उम्मीद न के बराबर है कि यह 2022 से पहले महामारी से पहले वाले स्तर को छू पाएगी। कीमतों पर न्यून दबाव के साथ 2021 में औसत मुद्रास्फीति दर 1.3% और 2022-25 के दौरान 1.5% बने रहने की संभावना है। पिछले वर्ष 1 यूरो की कीमत 1.23 यूएस डॉलर के समतुल्य रही थी। किन्तु 2021 की पहली तिमाही में लगातार गिरते हुए मार्च के अंत में इसका मूल्य 1.17 यूएस डॉलर हो गया। अर्थव्यवस्था में थोड़ा और सुधार आने के साथ वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले यूरो में कुछ मजबूती आने की संभावना है। किन्तु 2022-23 के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले यूरो में दोबारा गिरावट आने की आशंका है। क्योंकि ईसीबी अपनी अत्यधिक नरम मौद्रिक नीति को फेडरल रिज़र्व की अपेक्षा अधिक लंबे समय तक बनाए रखता है और इसके चलते यूएस के साथ ब्याज दर अंतर बढ़ेगा और यूरो में गिरावट आएगी। फ्रांस का चालू खाता घाटा भी 2019 में जीडीपी के 0.7% की तुलना में 2020 में बढ़कर जीडीपी के 1.9% के समतुल्य हो गया। यह कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के चलते बिगड़ते व्यापार घाटे और सेवा अधिशेष को दर्शाता है। विदेश व्यापार प्रवाह में सुधार आने से चालू खाता घाटा घटकर जीडीपी का 1.8% तक रहने की संभावना है।

यूनाइटेड किंगडम

कोविड-19 महामारी के चलते यूनाइटेड किंगडम को 2020 में भीषण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। इसकी वास्तविक जीडीपी में 9.9% की गिरावट आई। वैश्विक मांग में गिरावट आने से 2020 में निर्यात और आयात वृद्धि में भी तेजी से गिरावट आई और यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगे रहे। ये प्रतिबंध हटने और निवेश आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों से 2021 में वृद्धि दर 5.8% रहने की संभावना है। हालांकि ब्रेक्ज़िट संबंधी व्यवधानों से इसकी गति बाधित होने की आशंका है। 2020 में महामारी के चलते मांग में गिरावट आने से मुद्रास्फीति गिरकर औसतन 1% रही। 2021 में उपभोक्ता खर्च बढ़ने और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति संबंधी बाधाएं दूर होने से मुद्रास्फीति 3% रहने के आसार हैं। हाल के वर्षों में ब्रेक्ज़िट से संबंधित राजनीतिक अनिश्चितता और महामारी के चलते स्टर्लिंग का मूल्य अस्थिर रहा है। इसके साथ ही यूके का बड़ा चालू खाता घाटा भी एक कारण रहा, जिसे मुद्रा को सहयोग के लिए उल्लेखनीय रूप से अंतरराष्ट्रीय पूँजी निवेश की जरूरत होती है। 2021 में स्टर्लिंग में यूएस डॉलर के मुकाबले गिरावट की आशंका है। 2020 में एक स्टर्लिंग का मूल्य 1.28 यूएस डॉलर था, जिसके 2021 में 1.42 यूएस डॉलर रहने की संभावना है। चालू खाता घाटा 2020 में जीडीपी का 3.5% था, जिसके 2021 में बढ़कर जीडीपी का 4.5% रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंध बिगड़ने के चलते निर्यात क्षेत्र में कमजोरी है।

सेनेगल

कोविड-19 महामारी के चलते सेनेगल का वास्तविक जीडीपी 2020 में 0.5% की दर से बढ़ा। यह एक दशक से अधिक समय में सेनेगल की सबसे धीमी वृद्धि दर है। 2020 में औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 2.5% हो गई, जो 2019 में 1.8% थी। मुद्रास्फीति में यह बढ़ोत्तरी महामारी और स्थानीय बाढ़ के कारण आपूर्ति-श्रृंखला में आए व्यवधानों के चलते रही। हालांकि 2021 में इसके घटकर 2% रहने की उम्मीद है, क्योंकि उपर्युक्त औसत अनाज उत्पादन से खाद्यान्न की कीमतें गिरने की संभावना है। 2021 में विदेशी मांग के बढ़ने, हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के निर्माण और स्वर्ण खनन क्षेत्र में नए उत्खनन तथा विस्तार से सेनेगल की आर्थिक वृद्धि 2021 में बढ़कर 3% होने की उम्मीद है। 1 यूरो के मुकाबले सीएफए फ्रैंक का मूल्य 655.97 रहा और यूरो तथा यूएस डॉलर में उतार-चढ़ाव से इसमें भी उतार-चढ़ाव आया। 2020 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले सीएफए फ्रैंक का मूल्य 575.6 रहा था, जिसके 2021 में कुछ मजबूत होकर 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 542.1 सीएफए फ्रैंक रहने की उम्मीद है। चालू खाता घाटा भी 2020 में जीडीपी के 12.3% के स्तर से घटकर 2021 में जीडीपी का 10.9% रहने के आसार हैं। चालू खाता घाटे में यह सुधार पर्यटन राजस्व और कामगारों के रेमिटेंस के चलते आंका जा रहा है।

त्रिनिदाद एवं टोबैगो

2020 में 7.6% की गिरावट का सामना करने के बाद, कोविड-19 महामारी का प्रकोप कुछ कम होने और तेल एवं गैस उत्पादन में सुधार आने से 2021 में जीडीपी के 3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तथापि, जीडीपी के 2024 तक ही महामारी से पहले वाले स्तर पर पहुंचने के आसार हैं। 2020 में औसतन 0.6% रहने के बाद मुद्रास्फीति में भी मामूली बढ़ोत्तरी की संभावना है और 2021-25 के दौरान यह औसतन 1.2% रह सकती है। अर्थव्यवस्था पर आपूर्ति के मोर्चे पर मुद्रास्फीति दबाव बना हुआ है और खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल के दामों से लगे झटके के चलते 2020 में घरेलू मुद्रा को गिरावट का सामना करना पड़ा। केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर को 2021-25 के दौरान 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 6.8 त्रिनिदाद एवं टोबैगो डॉलर के आसपास बनाए रखने की उम्मीद है। 2020 में तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते चालू खाता घाटा 2020 में जीडीपी का 4% हो गया। कमोडिटी बाजार में सुधार आने और निर्यातों के बढ़ने से 2022-25 के दौरान चालू खाता औसतन 2.7% रहने के आसार हैं और इसमें अधिशेष दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार भी बढ़ने की उम्मीद है और इसके लगभग 10.8 माह के आयात कवर के समतुल्य रहने की संभावना है, जो अन्य कैरिबियाई देशों की तुलना में उच्चतर है। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

A$ ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को गत वित्तीय वर्ष में कोरोना वायरस से आर्थिक गिरावट के चलते लगभग 30 वर्षों में पहली बार मंदी का सामना करना पड़ा। जबकि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होता रहा है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा खर्च बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में रफ्तार पकड़ी और यह पुनः अपने पिछले वर्ष के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रही। यहां की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार जारी है और इसकी वृद्धि दर कोविड-19 से पहले के स्तर से अधिक हो जाने की संभावना है। कमोडिटी मांग के दुनियाभर में बढ़ने और उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा खर्च बढ़ने से वृद्धि दर बढ़ने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर फरवरी 2021 में तीन वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर रहने के बाद से यूएस डॉलर के मुकाबले अस्थिर बना हुआ है। 2021 की शुरुआत में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य 0.7693 रहा। त्वरित सुधार के साथ यह 0.7820 हो गया, किन्तु यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से यूएस डॉलर का मूल्य बढ़ गया और फरवरी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य गिरकर 0.7562 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि फरवरी के आखिरी में तांबे की कीमतें 10 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से 1 यूएस डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.8007 के स्तर पर रहा। फिर मार्च के अंत तक इसका मूल्य गिरकर 0.7586 रह गया और अप्रैल में तांबा बाजार में उफान के साथ यह 0.7817 रहा। विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष कमोडिटी कीमतें बढ़ने और वैश्विक आर्थिक सुधार से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और मजबूत होगा। 14 जून, 2021 को 1 यूएस डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य 0.7711 रहा।

संयुक्त अरब अमीरात दिरहम

Dh संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) विनिमय दर की दृष्टि से दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। यह यूएस डॉलर के मुकाबले 1973 से स्थिर रही है। 1997 से 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य 3.6725 एईडी के आसपास ही रहा है। इसकी मुद्रा में यह स्थिरता इसके तेल उद्योग पर निर्भरता के कारण रही है, जहां तेल के दाम यूएस डॉलर में निर्धारित किए गए हैं। 14 जून, 2021 को 1 यूएस डॉलर के मुकाबले एईडी का मूल्य 3.6728 रहा।

कोरोना वायरस संकट ने पिछले साल इस खाड़ी देश को भी प्रभावित किया। तेल की कीमतों में गिरावट आई और साथ ही पर्यटन जैसे गैर-तेल क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि यहां के केंद्रीय बैंक को 3.5% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ 2022 तक पूर्ण रिकवरी की उम्मीद है। इस वर्ष अक्टूबर से मार्च 2022 तक दुबई एक्सपो वर्ल्ड फेयर जैसे कार्यक्रम होने हैं। इससे अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलेगा। चूंकि यूएई इस क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन, ट्रांजिट और व्यापार केंद्र है, अतः इसे इन कार्यक्रमों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

मलेशियाई रिंगित

RM मलेशियाई अर्थव्यवस्था में बीते कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही थी। 2018 में इसकी वृद्धि दर 4.8% थी, और 2019 में 4.3% रही। किन्तु, 2020 में कोविड-19 महामारी के साथ-साथ सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक और निजी निवेश न्यूनतर रहने से अर्थव्यवस्था में 6% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 2021 में यहां की अर्थव्यवस्था में अच्छे सुधार की संभावना है और 2022 में इसके स्थिर होने की उम्मीद है।

दो सप्ताह की राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की शुरुआत में मलेशिया की मुद्रा रिंगित में स्थायित्व देखा गया और इससे यह संकेत मिला कि प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव यथासंभव सीमित ही रहेगा। हालांकि मई में रिंगित एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही। मई में देश में कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने से यूएस डॉलर के मुकाबले इसमें तकरीबन 1% की गिरावट आई। तथापि, यह 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 4.16 रिंगित के मार्च के अपने न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं गई। उसके बाद से मलेशिया में वर्तमान तालाबंदी के बावजूद यह एक यूएस डॉलर के मुकाबले 4.13 के स्तर पर बनी हुई है। 14 जून, 2021 को 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य 4.1130 रहा।

गिनी फ्रैंक

Gnf गिनी की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के दौरान मंदी रही है। वास्तविक जीडीपी 5.2% रहा। हालांकि 2019 के 5.6% के मुकाबले यह मामूली गिरावट ही रही। यह उल्लेखनीय प्रदर्शन 2020 में खनन गतिविधि में 18.4% की अच्छी बढ़त के कारण रहा। खनन क्षेत्र में 2019 में 8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके साथ ही चीन से बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की मांग बढ़ना भी एक कारण रहा, क्योंकि गिनी 2017 से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर चीन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। लेकिन महामारी से गैर-खनन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, जिनमें वृद्धि 2019 की 5.1% की तुलना में 2020 में 2.1% ही रही। इसके मुख्य कारण प्रमुख परियोजनाओं में देरी होना, सीमाओं का अस्थायी रूप से बंद रहना और कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपाय करना रहे, जिनसे कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र प्रभावित हुए।

यूएस डॉलर के मुकाबले गिनी फ्रैंक में कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से ही गिरावट आती रही है। गिनी द्वारा इबोला महामारी घोषित किए जाने के बाद फरवरी 2021 में गिनी की मुद्रा गिनी फ्रैंक गिरकर 10098 के स्तर पर रही। हालांकि उसके बाद यह कुछ संभली और 14 जून, 2021 को 9756 के स्तर पर रही। ■

एक्ज़िम मित्र

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और व्यापार वित्त, ऋण बीमा सुविधाओं तथा भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार संबंधी अन्य जानकारियों की उपलब्धता में विषमता को कम करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक्ज़िम मित्र नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की। एक्ज़िम मित्र निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता और व्यापार संबंधी जानकारी देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम करता है। एक्ज़िम मित्र भारतीय उद्यमियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मिलने वाले सवालों को हल करने में मदद करता है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

शिपमेंट व्यापक जोखिम नीति संबंधी जानकारी

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और व्यापार वित्त, ऋण बीमा सुविधाओं तथा भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार संबंधी अन्य जानकारियों की उपलब्धता में विषमता को कम करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक्ज़िम मित्र नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की। एक्ज़िम मित्र निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता और व्यापार संबंधी जानकारी देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम करता है। एक्ज़िम मित्र भारतीय उद्यमियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मिलने वाले सवालों को हल करने में मदद करता है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

आमतौर पर, शिपमेंट व्यापक जोखिम नीति को मानक नीति के रूप में जाना जाता है। ये नीतियां भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करने के लिए ईसीजीसी द्वारा जारी की जाती हैं। मानक नीति, अल्पकालिक ऋण यानी अधिकतम 180 दिनों के लिए दिए जाने वाले ऋण पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में जोखिमों को कवर करने के लिए उपयुक्त है। यह नीति शिपमेंट की तारीख से वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों जोखिमों को कवर करती है। यह उन निर्यातकों के लिए है जिनका निर्यात कारोबार अगले 12 महीनों के लिए ₹50 लाख से अधिक का होने की संभावना होती है। निम्नलिखित वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिम मानक नीति के तहत कवर किए जाते हैं।

वाणिज्यिक जोखिम

- क्रेता का दिवालियापन
- एक निर्दिष्ट अवधि, सामान्यतः देय तिथि से चार महीने की अवधि के अंदर क्रेता द्वारा भुगतान न कर पाने की स्थिति
- किसी निश्चित परिस्थिति के चलते क्रेता द्वारा माल न ले पाना

राजनीतिक जोखिम

- क्रेता के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना या सरकार की किसी कार्रवाई के चलते क्रेता द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के लेनदेन को रोकना या उसमें देरी करना।
- क्रेता के देश में युद्ध, गृह युद्ध, क्रांति या किसी तरह की नागरिक अशांति का होना।
- नए आयात पर प्रतिबंध लगाना या आयात का वैधता लाइसेंस रद्द करना।

विदेशी प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में माल की बिक्री की प्रक्रिया

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को विदेशों में अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए फेमा विनियमों, 2000 के विनियम 7 (7) के जरिए सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। निर्यातक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में माल की बिक्री द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा कर सकते हैं और भारत से बाहर रहने के दौरान इस खाते का संचालन भी कर सकते हैं, बशर्ते कि खाते में शेष राशि प्रदर्शनी/व्यापार मेले के बंद होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत को स्वदेश भेज दी जाए और संबंधित विज्ञापन श्रेणी-I बैंकों को पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।

स्कोमेट प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले ई-दस्तावेजों की जानकारी

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं:

- उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी फर्मों/संस्थाओं से अंतिम उपयोग के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) (उनके पत्र शीर्ष पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित);
- वस्तु / उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को दौरान शामिल फर्म (फर्मों) के खरीद आदेश (आदेशों) की प्रतिलिपि;
- आयात-निर्यात फॉर्म (एएनएफ)-1 (निर्यातक की प्रोफाइल);
- निर्यात की जाने वाली वस्तु से संबंधित विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं;
- आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट / करार की प्रतिलिपि (यदि दस्तावेज बहुत अधिक मात्रा में हैं, तो केवल वही हिस्से प्रस्तुत किए जाएं जो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी के लिए प्रासंगिक हों, और जिनमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तु (ओं) का उल्लेख हो; अतः दस्तावेजों के रूप में 10 पेज से ज्यादा अपलोड न किए जाएं।)
- यदि किसी माल के लिए पुनः आवेदन किया गया है तो इसी उत्पाद के लिए डीजीएफटी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि

निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी (कागजी प्रतिलिपि) डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत करनी होगी:

- मूल अंतिम उपयोग के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी);
- पिछले एक साल के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं के लिए आयातक देश में प्रवेश के बिल की प्रतिलिपियां

आईटीसी एचएस कोड सूची या भारत हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम कोड संबंधी जानकारी

आईटीसी-एचएस कोड को दो अनुसूचियों में बांटा गया है। आईटीसी (एचएस) आयात अनुसूची I में आयात नीतियों से संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों का वर्णन है, जबकि अनुसूची II में निर्यात नीतियों से संबंधित नियमों और नियमन का वर्णन है।

आईटीसी-एचएस कोड की अनुसूची-I को 21 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ग को अध्यायों में बांटा गया है। अनुसूची-I में 98 अध्याय हैं। इन अध्यायों को आगे सब-हेडिंग में विभाजित किया गया है, जिनके तहत विभिन्न एचएस कोड का उल्लेख किया गया है। आईटीसी-एचएस कोड की निर्यात नीति अनुसूची-II में 97 अध्याय हैं, जिनमें निर्यात नीतियों से संबंधित दिशा-निर्देशों का विवरण दिया गया है।

कमोडिटी विवरण, निष्क्रिय हो चुके कोड को निकाल देना, नए कोड जोड़ना, उत्पाद विवरण में परिवर्तन आदि को इन नियमों को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में चल रही प्रक्रिया के चलते समय-समय पर लिया गया है। ■

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

वस्तु व्यापार

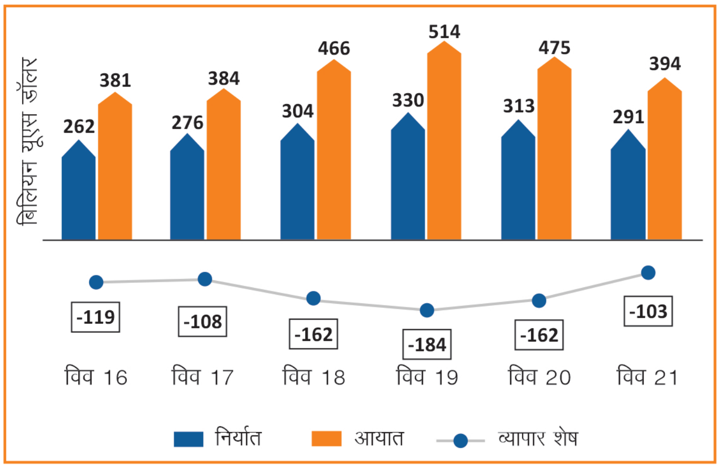

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवाएं व्यापार

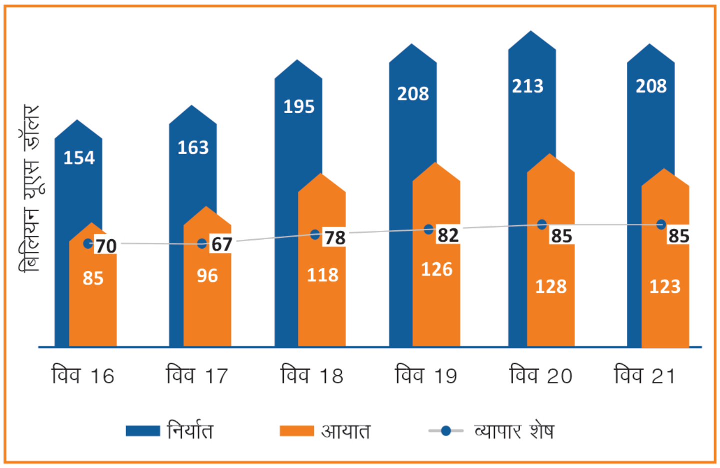

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह

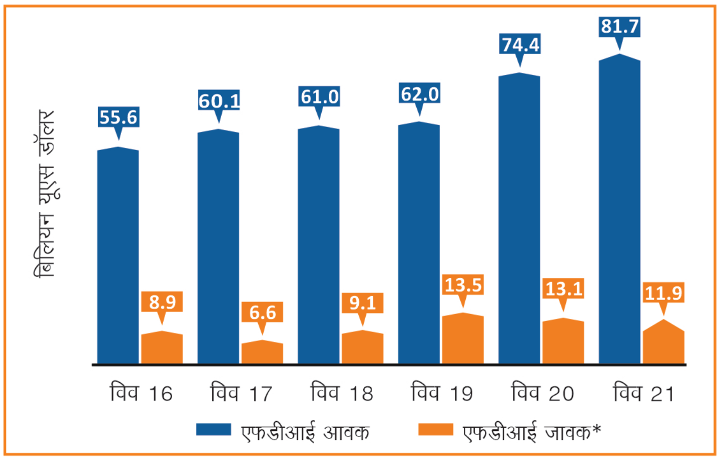

नोट: - एफडीआई जावक में इक्विटी, ऋण और इन्वोक की गई गारंटियां शामिल हैं।*

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)

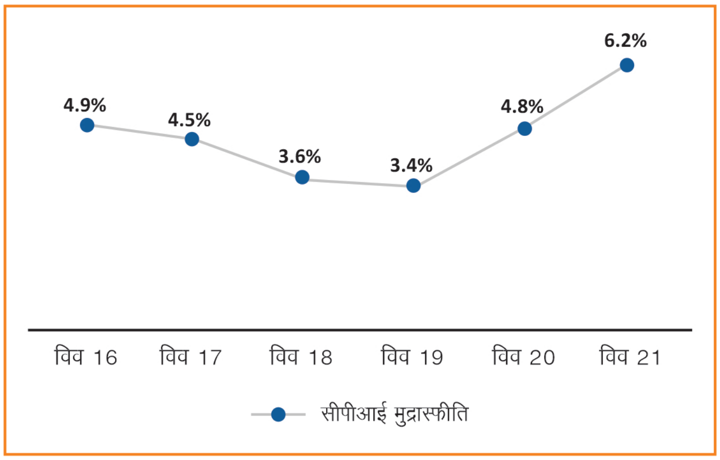

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा (सीएडी)

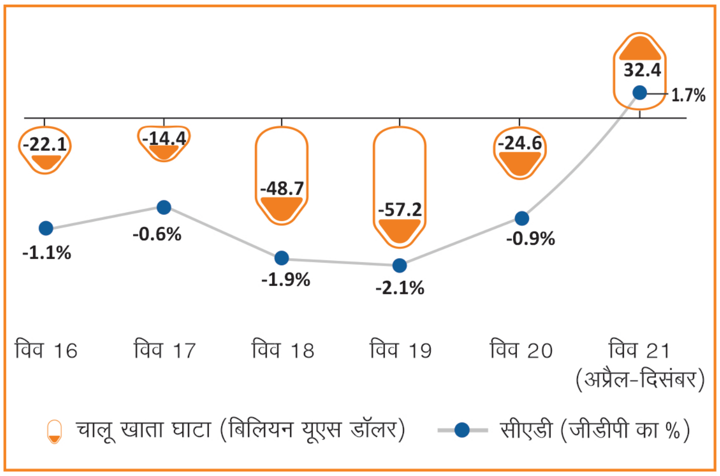

स्रोत: आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

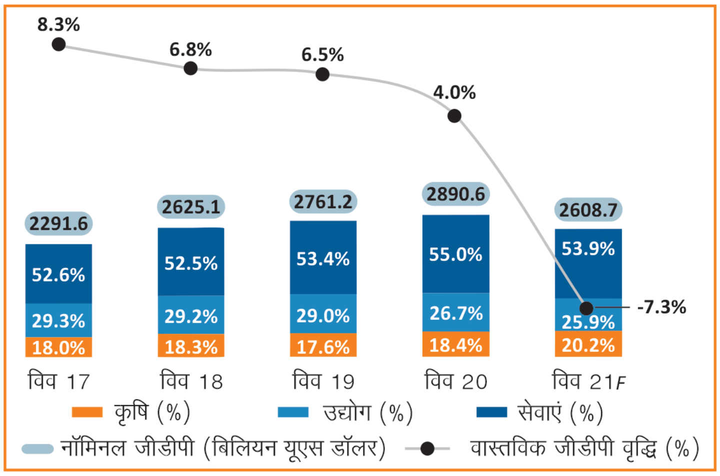

नोट: F अग्रिम पूर्वानुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार